



प्रीलमिस फैक्ट्स : 05 जुलाई, 2018

वशिवास पटेल बने भारतीय भुगतान परिषद के चेयरमैन
(Vishwas Patel appointed Payments Council of India Chairman)

- वशिवास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद (Payments Council of India) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
- पीसीआई भुगतान और नपिटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है।
- वशिवास पटेल ने नवीन सूर्या का स्थान लिया है।
- इससे पूर्व वशिवास पटेल पीसीआई के सह-अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे थे तथा 2013 से ही परिषद से जुड़े हुए थे।
- भारतीय भुगतान परिषद का गठन वर्ष 2013 में डिजिटल भुगतान उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में किया गया था।

जलभराव प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम एआई सॉल्यूटम का विकास
(New AI may prevent waterlogging)

- हाल ही में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NSIT) के छात्रों की टीम ने एक एआई प्रणाली विकसित की है, जो जलभराव प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर सकती है।
- इस प्रणाली के विकास से बड़े शहरों में बरसात के मौसम में होने वाली जाम की समस्या से बचा जा सकता है।
- इस प्रणाली के विकास में शोधकर्ताओं ने सुभेद्य क्षेत्रों में जलभराव की गंभीरता का पता लगाने के लिये वर्षा, यातायात और स्थान संबंधी आँकड़ों की सहायता ली।
- इस प्रणाली के विकास हेतु आरंभिक अध्ययन फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुआ था, क्योंकि वहाँ की पर्यावरणीय स्थितियाँ भारत के शहरों के समान हैं।
- इस प्रणाली का उपयोग शहरों में दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के निर्धारण हेतु भी किया जा सकता है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में एम्बुलेंसों की तैनाती की जा सकती है। साथ ही यातायात पर त्रयोहारों और अवकाश दविसों के प्रभाव का आकलन भी किया जा सकता है।

भारत नरिवाचन आयोग ने कथि 'सीवजिलि' मोबाइल एप लॉन्च
(Election Commission of India launches Mobile App 'cVIGIL')

मुख्य नरिवाचन आयुक्त श्री ओ पी रावत ने हाल ही में नरिवाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा तथा श्री अशोक लवासा के साथ चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहति के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिये 'सीवजिलि' एप लॉन्च किया।

- 'सीवजिलि' एप यूज़र्स फ्रेंडली और एन्ड्रॉयड एप्लिकेशन संचालन में काफी आसान है।
- यह एप उन्हीं स्थानों पर चालू होगा, जहाँ चुनाव की घोषणा की गई है।
- एप का बीटा वर्ज़न लोगों तथा चुनावकर्मियों के लिये उपलब्ध होगा, ताकथे लोग इसकी विशेषताओं से परिचित हो सकें और डमी डाटा भेजने का प्रयास कर सकें।
- परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसे सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा इस्तेमाल के लिये उपलब्ध कराया जाएगा। यह उपलब्धता छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मज़ोरम तथा राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव से ही होगी।
- चार राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान एप का व्यावहारिक उपयोग, अगले लोकसभा चुनाव के दौरान इसके व्यापक रूप में उपयोग के पहले पायलट प्रयास के रूप में काम करेगा।
- इस एप में दुरुपयोग रोकने की अंतर्निहित विशेषताएँ हैं। यह एप केवल आदर्श आचार संहति उल्लंघन के बारे में शिकायत प्राप्त करता है।

- तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूज़र्स को रपॉर्ट करने के लिए पाँच मिनट का समय मलिया ।
- कसिी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिये एप पहले से रपॉर्ट कयि गए या पहले ली गई तस्वीरों या वीडियो अपलोड करने की अनुमतति नहीं देगा । इस एप में 'सीवजिलि' एप का इस्तेमाल करते हुए फोटो और रकिॉर्डेड वीडियो को फोटो गैलरी में सेव करने की सुवधि नहीं होगी ।
- यह एप चुनाव वाले राज्यों से नागरकि के बाहर नकिलते ही नषिक्रयि हो जाएगा ।

वापकोस का 50वाँ स्थापना दविस
(WAPCOS celebrated 50th foundation day)

- हाल ही में जल एवं वदियुत परामरश सेवा (WAPCOS) का 50वाँ स्थापना दविस मनाया गया| स्थापना दविस समारोह नई दल्लिी स्थति प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजति कयिा गया|
- भारत सरकार ने वर्ष 1969 में वापकोस का गठन एक सार्वजनकि कषेत्र की कंपनी के रूप में कयिा था|
- जल संसाधन, नदी वकिस व गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत यह एक तकनीकी-वाणजियकि संगठन है ।
- वर्तमान में वापकोस को एक मनिरित्न कंपनी का दर्ज़ा प्रापत है|
- वापकोस, भारत तथा वदिशों में जल संसाधन, वदियुत तथा अवस्थापना कषेत्र में परामरशी सेवाएँ उपलब्ध करवाता है ।
- हाल ही में अपनी संस्था के अंतर्नयिम में संशोधन कर वापकोस ने वशिव में वकिसात्मक परयोजनाओं हेतु प्रवर्तन सेवाओं की संकल्पना उपलब्ध करवाने के लयि स्वयं को अनुकूल बनाया है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prelims-fact-05-07-2018>

